साप्ताहिक
जागत गांव हमार
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक
RNI-MPHIN/2015/72544
चौपाल से भोपाल तक
भोपाल, सोमवार, 04-10 नवंबर 2024 वर्ष-10, अंक-29
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

प्रदेश के 10 श्रेष्ठ गौ-पालक सम्मानितः सीएम ने की गोवर्धन पूजा, कहा- सरकार उठाएगी गायों के पालन-पोषण का खर्च

गौ-पालकों को अनुदान के साथ सरकार देगी क्रेडिट कार्ड बूढ़ी-अपाहिज गायों की देखभाल अब गौ-शालाओं में होंगी

» गौ-वंश के बेहतर आहार के लिए प्रति गौ-वंश की राशि की जाएगी दोगुनी

» सीएम डॉ. यादव ने राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा समारोह को किया संबोधित

» गाय धार्मिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से भारतीयों के लिए पूजनीय

» गौपालन और दुग्ध उत्पादन करने वालों को मिलेगा बोनस

» पशुधन के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाता गोवर्धन पूजा पर्व

» अब गौवध के दोषियों को मिलेगा 7 वर्ष का सख्त कारावास

» अगली पशु गणना में प्रदेश को तीसरे से नम्बर वन बनाएंगे

» प्रदेश में गौ-वंश संरक्षण के लिए हो रहे विशेष प्रयास

» दुग्ध उत्पादन में प्रदेश को लाएंगे पहले स्थान पर

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश में गौ-पालन को बढ़ावा देकर किसानों और गौ-पालकों की आर्थिक सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है। शहरों में कांजी हाऊस के स्थान पर गौ-वंश की देखभाल के लिए गौशालाएं प्रारंभ की जाएगी। प्रदेश के 51 हजार से अधिक ग्रामों में दूध का उत्पादन बढ़ाते हुए इस क्षेत्र में मध्यप्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान पर लाने का प्रयास है। इसके साथ ही अगली पशुगणना में प्रदेश पहले तीसरे स्थान से पहले स्थान पर लाने के के समस्त प्रयास भी किए जाएंगे। यह बात सीएम डॉ. मोहन यादव ने रवींद्र भवन परिसर भोपाल में राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा समारोह के दौरान कही। इसके साथ ही सीएम ने प्रदेश के दस श्रेष्ठ गौ-पालकों को सम्मनित भी किया। इसमें मऊगंज जिले के गौ-पालक सौखीलाल यादव, इंदौर की गौशाला के संचालक हरिओम आनंद, गायत्री परिवार से जुड़े सूरज सिंह परमार, सोनू जैन, प्रदीप कुमार जैन और उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर आदि नगरों के अन्य गौशाला संचालक शामिल रहे। सीएम ने कहा कि प्रदेश में गौ-वंश पालन पर क्रेडिट कार्ड देने की पहल की गई है। किसान और पशुपालक दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा करते हैं। प्रदेश में पहली बार शासन स्तर पर गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति और गौ-माता के प्रति सम्मान की भावना को सशक्त करना है।

लौह पुरुष के किया स्मरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से अनुबंध कर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की रणनीति तैयार की गई है। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने दुग्ध सहकारिता आंदोलन को गति दी थी। आज अमूल के उत्पाद देश-विदेश में लोकप्रिय हैं। दूध, घी और मक्खन के साथ गौ-काष्ठ का भी उपयोग हो रहा है। गोबर से खिलौने और कलाकृतियां तैयार की जा रही हैं। प्रदेश सरकार गौ-पालन को प्रोत्साहित करने के लिए गौ-शाला को प्रति गाय 20 रुपए के स्थान पर 40 रुपए के अनुदान का निर्णय ले चुकी है।

पालकों को विशेष अनुदान

सीएम ने कहा कि जो पशुपालक 10 या उससे अधिक गायों का पालन करेंगे उन्हें भी विशेष अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 9 प्रतिशत उत्पादन हो रहा है, जिसे 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी गांव में दुग्ध संघ के माध्यम से गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी। प्रारंभ में 11 हजार गांव में दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि का प्रयास है। प्रदेश में इस वर्ष गौ-वंश रक्षा पर्व मनाया जा रहा है।

गौ-वध पर सख्त सजा

मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ-वंश से समृद्ध प्रदेश में गौ-माता के संरक्षण के लिए समुचित प्रावधान किए जा रहे हैं। गौ-वध को रोकने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। गौ-वध का दोषी पाएजाने पर 7 वर्ष की सख्त सजा देने का कानूनी प्रावधान है।

मप्र गौ-वंश में समृद्ध

मप्र गौ-वंश में समृद्ध है। प्रदेश में 1 करोड़ 39 लाख गाय हैं। 2019 की पशु गणना के अनुसार मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। हम अगली पशुगणना में देश में प्रथम स्थान पर आने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने गौ-पालकों को प्रोत्साहन, गौ-वंश संरक्षण के सरकार के प्रयासों और योजनाओं की जानकारी दी। मप्र में पशु चिकित्सा के लिये गौ-एंबुलेंस का संचालन भी किया जा रहा है।

देश की अर्थव्यवस्था में सहयोगी गौ-पालन

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए मध्यप्रदेश गौ-वंश संरक्षण सहित अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। भारत विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। शीघ्र ही भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। ग्रामों में कृषि कार्य के साथ पशुपालन एवं गौ-पालन किसान की आर्थिक समृद्धि में सहयोगी है। शहरों में भी गौपालन से पशुपालक अपनी आय बढ़ा सकते हैं। मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहा है। पशुधन संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। गोवर्धन पूजा हमारी संस्कृति की प्रतीक भी है, जिससे विश्व में भारत की पहचान है।

शहरों में होंगी बड़ी गौ-शालाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि गौपालन और संरक्षण के कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर जैसे शहरों में जहाँ हजारों की संख्या में गौ-वंश है, बड़ी गौशालाएं प्रारंभ की जायेगी। शहरों की गौशालाओं में 5 हजार से लेकर 10 हजार तक गौवंश को रखने की व्यवस्था होगी। राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में पशुधन संरक्षण और पशुपालन के लिए 590 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है।

शहद उत्पादन में दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल

शहद के उत्पादन में मध्यप्रदेश-उत्तर प्रदेश देश में अव्वल

भोपाल। जागत गांव हमार

शहद का सेवन तो सभी लोग करते हैं। शहद में कई आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि शहद का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। यानी कहां से पूरे देश में सबसे अधिक पहुंचता है शहद। इसके लिए पढ़ें **जागत गांव हमार** की विशेष रिपोर्ट...। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में शहद का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। यह जिला चंबल घाटी में राज्य की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर स्थित है। मुरैना जिले में शहद के अलावा सरसों का उत्पादन भी होता है। वहीं भारत में सबसे अधिक शहद का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। यानी शहद उत्पादन के मामले में ये राज्य सबसे आगे है। यहां के किसान हर साल बंपर शहद का उत्पादन करते हैं। देश के कुल शहद उत्पादन में यूपी का अकेले का 18 फीसदी का योगदान है। शहद प्राकृतिक चिपचिपा, मीठा पदार्थ है जिसे मधुमक्खियां फूलों के रस से बनाती हैं। वहीं, शहद उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। देश के कुल शहद उत्पादन में इस राज्य की हिस्सेदारी 16 फीसदी है। शहद स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी माना जाता है। इसे लोग बड़े ही चाव से खाते हैं।

पंजाब तीसरे और बिहार चौथे पायदान पर

वहीं, उत्पादन के मामले में भारत के टॉप तीन राज्यों में तीसरा नंबर पंजाब का है। यहां शहद का 13.60 फीसदी उत्पादन होता है। शहद में प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन, एंजाइम, खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं, बात करें उत्पादन की तो चौथे स्थान पर बिहार है। देश के कुल शहद उत्पादन में इस राज्य की हिस्सेदारी 12.80 फीसदी है। शहद सर्दी, जुकाम, खांसी की समस्या में सहायक माना जाता है। साथ ही मौसमी बीमारियों से बचने के लिए शहद का उपयोग फायदेमंद है। वहीं, उत्पादन में पांचवें पायदान पर राजस्थान है। यहां शहद का 8.96 फीसदी उत्पादन होता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (2023-24) के आंकड़ों के अनुसार शहद के पैदावार में छठे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है। यहां के किसान हर साल 4.68 फीसदी शहद का उत्पादन करते हैं। वहीं, ये छह राज्य मिलकर 75 फीसदी शहद का उत्पादन करते हैं।

मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच लगभग 216 किलोमीटर लम्बी सीमा रेखा भी बनाती है, देश की सबसे स्वच्छ यह नदी

सिर्फ दो राज्यों की सीमाओं को विभाजित करने वाली नदी नहीं, पौराणिक इतिहास की गाथा है चंबल

चंबल उत्तर उत्तर-मध्य भाग से धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना से राजस्थान में करती प्रवेश

श्योपुर। जागत गांव हमार

चम्बल वो नदी है जो मध्य प्रदेश की मशहूर विंध्याचल पर्वतमाला से निकलकर युमना में मिलने तक अपने 1024 किलोमीटर लम्बे सफर में तीन राज्यों को जीवन देती है। हम अपने नजरिए से देखें तो चंबल नदी हमें राजस्थान और मध्य प्रदेश से विभाजित करने वाली रेखा है लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि यह दो राज्यों कि सीमाओं को विभाजित नहीं बल्कि जोड़ने का मुख्य साधन है। भारत की सबसे स्वच्छ नदियों में शुमार चंबल का पौराणिक इतिहास भी है। महाभारत से रामायण तक हर महाकाव्य में दर्ज होने वाली चम्बल राजस्थान की सबसे लम्बी नदी है। श्रापित और दुनिया के सबसे खतरनाक बीहड़ के बागियों का घर माने जाने वाली चम्बल नदी अब दस्यु मुक्त होकर मगरमच्छों और घड़ियालों का गढ़ बन गई है।

भारत की सबसे साफ और स्वच्छ नदियों में से एक चम्बल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू छावनी के निकट स्थित विंध्य पर्वत श्रृंखला की जनापाव पहाड़ियों के भदकला जलप्रपात से निकलती है और इसे ही चम्बल नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। चम्बल मध्य प्रदेश में अपने उद्गम स्थान से उत्तर तथा उत्तर–मध्य भाग में बहते हुए धार, उज्जैन, रतलाम, मन्दसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलों से होकर राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में चम्बल चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ से बहती हुई कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करोली और धौलपुर जिलों से निकलती है। जिसके बाद ये राजस्थान के धौलपुर से दक्षिण की ओर मुड़ कर उत्तरप्रदेश में भरेह के पास पचनाडा मेंकी यमुना में मिल जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पचनाडा वह स्थान है जहां पांच नदियां मिलती हैं, इन पांच नदियों में क्वारी, चंबल, सिंध, यमुना और पहुज शामिल हैं। यमुना में शामिल होने के पहले चम्बल नदी उत्तर पूर्व में बहते हुए कई भौतिक विशेषताओं और सभी प्रकार के इलाकों को पार करते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सैकड़ों किलोमीटर लम्बी सीमा रेखा भी बनाती है।

मप्र राजस्थान के बीच 216 किमी सीमाओं की परिक्रमा करती है चंबल– विंध्य पर्वतमाला से निकलने वाली भारत की एकलौती प्रदूषण से मुक्त नदी चम्बल अपने उद्गम स्थान से विलय तक कुल 1024 किलोमीटर लम्बी है। इसकी इस विशाल लम्बाई का लगभग 376 किलोमीटर मध्यप्रदेश और करीब 249 किलोमीटर राजस्थान में पड़ता है। इसके साथ ही यह विशाल नदी मध्यप्रदेश से राजस्थान में प्रवेश से पहले दोनों राज्यों के बीच लगभग 216 किलोमीटर लम्बी सीमा रेखा भी बनाती है। जिसके बाद चम्बल करीब 150 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तरप्रदेश पहुंचती है, जहां ये जालौन जिले में 123 मीटर की ऊंचाई पर यमुना नदी में मिलने से पहले यह लगभग 33 किलोमीटर तक ओर फैलती है। यहां यह क्वारी, सिंध और पहुज के साथ यमुना में विलय हो जाती है, इन नदियों के इस संगम को वृहद गंगा जल निकासी प्रणाली में इसके एकीकरण का प्रतीक भी माना जाता है।

चंबल की सहायक नदियां

चम्बल नदी की सहायक नदियों में मुख्य रूप से आहू नदी, मांगली नदी, गुंजाली नदी, कुराल नदी, चाकण नदी, घोड़ा पछाड़ नदी, मेज नदी, क्षिप्रा नदी, बनास नदी, ब्राह्मणी नदी या बामणी नदी, कूनो नदी या कूनो नदी, सीप नदी, पार्वती नदी, परवन नदी, नेवाज या निवाज नदी और काली सिंध नदी शामिल है। चम्बल की सहायक नदियों के इसमें विलय की बात करें तो, इसकी सहायक नदियों के चम्बल में विलय की शुरुआत मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के विलय से होती है। राजस्थान में इसका पहले संगम झालावाड़ में आहू नदी के कालीसिंध नदी में मिलने से शुरू होता है। इन दोनों के संगम के बाद कालीसिंध बहते हुए कोटा पहुंचती है, जहां इसका चम्बल नदी में संगम होता है। कालीसिंध और आहू नदियों के इस संगम को सामेला कहा जाता है। इसके साथ झालावाड़ में ही चम्बल की सहायक परवन नदी में नेवाज या निवाज नदी का संगम भी होता है, जो आगे बहते हुए कोटा में चम्बल की सहायक कालीसिंध नदी में मिल जाती है। इसके बाद सवाई माधोपुर में पार्वती, सीप और बनास नदी सवाई माधोपुर के पदरा गांव के रामेश्वरम घाट पर चम्बल नदी में मिलती है, इनके इस संगम को त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। त्रिवेणी संगम में चम्बल में मिलने वाली बनास नदी को इसकी सबसे लम्बी सहायक नदी है। इसके साथ ही चम्बल नदी का कूनो नदी से भी संगम होता है। जिसके बाद चित्तौड़गढ़ में ब्राह्मणी नदी और बूंदी में मेज नदी का चम्बल में संगम होता है। मेज और चम्बल के संगम पर बूंदी जिले में मेज बांध भी बनाया गया है।

चंबल पर बना सबसे बड़ा बांध

चंबल एक वर्षा आधारित नदी है, जिसके चलते गर्मियों के महीनों के दौरान इसका जल स्तर काफी नीचे चला जाता है। लेकिन फिर भी इसमें अनुमानित रूप से लगभग 143,219 वर्ग किमी से अधिक का जल निकासी बेसिन है। इस बेसिन के चलते चम्बल नदी जलविद्युत शक्ति और सिंचाई के लिए भारत की सबसे उपयुक्त नदियों में से एक है। चम्बल की इसी खासियत के चलते इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। इसकी जलविद्युत शक्ति दोहन की बात करें तो इस पर कई बांध और बैराज बनाए गए हैं, जिसमे चंबल घाटी परियोजना के हिस्से के रूप में तीन बांध और एक बैराज शामिल हैं। चम्बल पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर गांधी सागर बांध, चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध और कोटा के पास जवाहर सागर बांध को बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जबकि कोटा बैराज को इन तीन बांधों से पानी को डायवर्ट करने और सिंचाई के लिए बनाया गया है। गांधी सागर बांध चम्बल नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है, जो चम्बल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है, जबकि इस नदी पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध है।

चम्बल की अर्थव्यवस्था और उद्योग

विधुत उत्पादन के साथ चम्बल के पानी से मध्य प्रदेश और राजस्थान की लगभग 7 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इसके चलते इसे राजस्थान के हाड़ोती की कामधेनु का नाम भी दिया गया है। चम्बल से होने वाली सिंचाई के चलते मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से सरसों, बाजरा, तिल, अरहर, सोरघम, ज्वार,रागी, उड़द, मूंग और कई फल व सब्जियों की खेती होती है तो वहीं इस नदी के पानी के राजस्थान के बीहड़ को उपजाव बनाने के चलते राजस्थान में मुख्य रूप से गेहू, सोयाबीन, चावल, तरबूज, मूंग, उड़द, मक्क ा, तिल, बाजरा, मूंगफली, गन्ना और गवार की बड़े स्तर पर खेती की जाती है। खेती अलावा चम्बल से पर्याप्त मात्रा में औद्योगिक जरूरतों के लिए पानी मिलने के चलते चंबल के किनारों पर बसे शहरों में कई उद्योग और रोजगार के साधन भी उपलब्ध हुए हैं। मध्य प्रदेश में चम्बल के किनारे बसे उज्जैन और नागदा में भी चम्बल के चलते कई बड़ी औद्योगिक इकाईयां स्थापित की गई है। भारत के जाने माने बिरला ग्रुप ने भी अपने बिज़नेस की शुरुवात उज्जैन ज़िले में स्थित नागदा में सीमेंट फैक्ट्री डालने से की थी। इसके साथ ही यहां कई बड़े और छोटे औद्योगिक उद्यम हैं, जिनमें मुख्य रूप से भारत की सबसे महत्वपूर्ण विस्कोस फ़ाइबर प्लांट कम्पनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, बायोमास ईंधन पर आधारित संयंत्र लैंक्सेस के साथ कई कागज, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, सीमेंट, इंजीनियरिंग, चीनी और फूड प्रोसेसिंग उद्योग शामिल है। चम्बल के किनारे बसे कोटा शहर में एशिया के सबसे बड़े उर्वरक संयंत्र में से एक चंबल फ़र्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स लिमिटेड और श्रीराम फ़र्टिलाइज़र्स, विश्वभर में सीमेंट की जानी मानी कम्पनी मंगलम सीमेंट, भारत की सबसे बड़ी ग्लास कंपनियों में से एक सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज, एशिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक इंस्ट्रूमेन्सन लिमिटेड, रेलवे वेगन बनाने फैक्ट्री सिमको बिरला के साथ कई थर्मल पावर प्लांट, पारंपरिक स्वदेशी उद्योग, सीमेंट, तिलहन मिलिंग, डेयरी, आसवन, धातु हस्तशिल्प, साड़ी, खनन और कोचिंग उद्योग शामिल है। इसके साथ ही कोटा जिले में ही विश्व की सबसे बड़ी धनिया मंडी भी मौजूद है।

चम्बल की वनस्पति और वातावरण

मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली चम्बल के विशाल वाटर बेसिन के चलते इसके किनारों पर एक चुनौतीपूर्ण वातावरण में अर्ध-शुष्क विस्तार से वनस्पति पनपती है। खड्डों की संरचनाओं और कांटेदार जंगलों के चलते इसके आसपास के जंगल और वनस्पतियों को उत्तरी उष्णकटिबंधीय वनों के तहत वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण आम तौर पर 600 से 700 मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों का संकेत देता है, जो कम शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। चम्बल का इलाका कंटीली झाड़ियों और छोटे पेड़ों से घिरा हुआ है जो समय के साथ यहां की परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तित हो गए हैं। चम्बल के किनारों पर 1000 से ज्यादा फूलदार पौधों की प्रजातियां, एनोजिसस लैटिफोलिया, ए. पेंडुला, टेक्टोना ग्रैंडिस, लैनिया कोरोमंडलिका, डायोस्पायरोस मेलानोक्सिलोन, स्टर्कुलिया यूरेन्स, मिट्रैग्ना पार्विफ्लोरा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, बोसवेलिया सेराटा, ब्रिडेलिया स्क्वैमोसा और हार्डविकिया बिनाटा पायी जाती हैं। यहां की वनस्पतियों में मुख्य रूप से कैपेरिस डिकिडुआ, कैपेरिस सेपियारिया, बालानाइट्स एजिपियाका, बबूल सेनेगल, ए. निलोटिका, ए. ल्यूकोफ्लोआ, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, मेटेनस इमर्जिनाटा, टैमरिक्स प्रजातियां, साल्वाडोरा पर्सिका, एस. ओलेओइड्स, ेटेलारिया मेडिकागिना, सी. बुरहिया, क्लेरोडेंड्रम फ्लोमिडिस शामिल हैं।

चम्बल के बीहड़ और डाकू

चम्बल नदी अपनी इन खासियतों के अलावा अपने बीहड़ के लिए भी काफी विख्यात या ये कहें की देशभर में कुख्यात रही है। सात जिलों के 2.19 लाख हैक्टेयर में फैला चंबल का बीहड़ एक समय में अपने कुख्यात डकैतों के लिए काफी चर्चा में रहा है। 70 के दशक में इन्हीं चंबल के बीहड़ों में प्रसिद्ध डाकू मलखान सिंह, पान सिंह तोमर, मुन्नी बाई, फूलन देवी, माखन सिंह, सुल्तान सिंह, रमेश सिंह सिकरवार, जैसे खूंखार डाकुओं की दहशत रही हैं। एक ज़माने में चम्बल के बीहड़ों का नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे, क्योंकि इन बीहड़ों में डकैत डेरा डाले रहते थे। यहां रहने वाले डकैत अपहरण, लूट, डकैती, हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। डकैतों के इन्ही किस्सों के चलते यहां कई फिल्में बनी हैं, जिसमे मुख्य रूप से पुतलीबाई, सुल्ताना, बैंडिट क्वीन, पानसिंह तोमर आदि फिल्में शामिल हैं जो यहां के डकैतों की जीवनी पर आधारित हैं। बीहड़ वो क्षेत्र होता है जो पानी के तेज बहाव और बरसात के चलते बार-बार अपनी आकृति बदलते रहता है। चंबल नदी की निकटता के कारण इसे चंबल के बीहड़ कहा जाता है। ये राजस्थान में धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उत्तर प्रदेश में इटावा, मध्यप्रदेश में मुरैना, भिण्ड, श्योपुर आदि जिलों तक बीहड़ फैला हुआ है। हालंकि चम्बल सिर्फ अपने डकैत ही कुख्यात नहीं हैं, बल्कि इसका पानी देश की अन्य नदियों के मुकाबले ज्यादा स्वच्छ और जलीय जीवों के अनुकूल होने के चलते, चम्बल में कई दुर्लभ और लुप्त होने की कगार पर खड़े जलीय जीवों और पक्षियों को संरक्षण मिल पाता है।

चम्बल घड़ियाल अभयारण्य

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, जो पर्यटकों के बीच चंबल बोट सफारी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रयासों से शुरू हुई एक प्रमुख घड़ियाल संरक्षण परियोजना है। इसकी शुरुवात साल 1978 में मध्यप्रदेश ने की थी, जिसे बाद में राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया। 5400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ यह अभ्यारण्य स्थलाकृति खड्डों, पहाड़ियों और रेतीले समुद्र तटों से भरा कथिअर-गिर शुष्क पर्णपाती वन पारिस्थितिकी क्षेत्र का हिस्सा है। चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य का मुख्य उद्देश्य लुप्तप्राय घड़ियाल, लाल मुकुट वाले कछुए और गंगा डॉल्फिन को संरक्षित करना है। इसके अलावा यहां मगरमच्छ, चिकने बालों वाले ऊदबिलाव, धारीदार लकड़बग्घा और भारतीय भेड़ियों को भी संरक्षित किया गया है। इस अभयारण्य में कछुवों की 26 दुर्लभ प्रजातियों में से 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। साथ ही यह अभयारण्य गंगा डॉलफिन के अंतिम मौजूदा घरों में से एक है और यहां एक हजार से ज्यादा घड़ियाल और 300 से ज्यादा दलदली मगरमच्छ भी रहते हैं। इन सब के अलावा यहां सांभर हिरण, नील गाय, भारतीय हिरन, रीसस बंदर, हनुमान लंगूर, भारतीय ग्रे और छोटे एशियाई नेवले, बंगाल लोमड़ी, पाम सिवेट, जंगली बिल्ली, जंगली सूअर, उत्तरी पाम गिलहरी, भारतीय कलगीदार साही, भारतीय खरगोश, भारतीय उड़ने वाली लोमड़ी और भारतीय लंबे कान वाले हाथी जैसे स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य प्रवासी और स्थानीय पक्षियों सहित लगभग 320 प्रजातियों का निवास स्थान हैं, जिसमें सारस क्रेन, पल्लास फिश ईगल, इंडियन कोर्सर पल्लीड हैरियर, लेसर फ्लेमिंगो, ब्लैक-बेलिड टर्न, रेड- क्रेस्टेड पोचार्ड, फेरुगिनस पोचार्ड, बार हेडेड गूज, ग्रेट थिकनी, ग्रेटर फ्लेमिंगो, डार्टर और ब्राउन हॉक उल्लू आदि शामिल हैं।

भैंसरोड़गढ़ अभयारण्य

229 वर्ग किलोमीटर में फैला ये अभयारण्य राजस्थान के चित्तौडगढ़ जिले में स्थित है, जिसे राजस्थान सरकार ने 5 फरवरी 1983 को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया था। इस जगह का मुख्य आकर्षण साल 1741 में रावत लाल सिंह द्वारा निर्मित रावतभाटा के पास स्थित विशाल भैंसरोड़गढ़ दुर्ग है, और इसी दुर्ग के नाम पर इस अभयारण्य का नामकरण भी किया गया है। ब्राह्मिनी एवं चम्बल नदियों के संगम पर बना ये जल दुर्ग राजस्थान के रियासतकाल में महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की सैन्य चौकी हुआ करता था। यह अभयारण्य बाघ, तेंदुए, सुस्त भालू, लकड़बग्घा और हिरणों की कई प्रजातियों सहित वन्यजीवों की एक विविध श्रेणी का घर है। इसके साथ ही यहां की वन्सपति की बात करें तो धोक यहां का मुख्य वृक्ष है, जबकि यहां सालार, कदम्ब, गुर्जन, पलाश, तेन्दु, सिरस, आमला, खैर, बेर सेमल आदि पेड़ों के साथ नम जगहों पर अमलतास, इमली, आम, जामुन, चुरेल, अर्जुन, बहेड़ा, कलम और बरगद प्रजाति के पेड़ भी मिलते हैं।

चम्बल का सामाजिक जीवन और जनजातियां

चम्बल नदी के किनारें व्यवसायिक केंद्रों, अभ्यारणों, मंदिरों, पर्यटक स्थलों और विकसित शहरों के साथ कई आदिवासी जंतियों व जनजातियों को भी अपने अंदर समेटे हुए हैं, जिनमें सबसे मुख्य भगोरिया, भीलाला, बारेला, पटेलिया, सहरिया, गोंड, भील और बंजारा है। चंबल नदी के किनारों पर कई तरह की संस्कृति, प्रथा, सभ्यता, परम्परा और रीती-रिवाज फैले हुए हैं, जिसमें भगोरिया उत्सव को सबसे मुख्य माना जाता है। जैसा की नाम से ही समझ आता है, भगोरिया यानि भाग कर अपने लिए अपनी पसंद से जीवन साथ चुन लेना होता है। इस उत्सव में हज़ारों की संख्या में युवा-युवतियां सज-धजकर पारंपरिक वस्त्रों में प्यार, शादी, व्यापार, सामाजिक सद्भाव के अलग-अलग रूप देखने को शामिल होते हैं। भगोरिया हाट-बाजारों में युवक-युवती बेहद सज-धजकर अपने भावी जीवनसाथी को ढूंढ़ने आते हैं। इनमें आपसी रजामंदी जाहिर करने का तरीका भी बेहद निराला होता है। सबसे पहले लड़का लड़की को पान खाने के लिए देता है। यदि लड़की पान खा ले तो इसे समझा जाता है कि लड़की ने हां कर दी है। फिर लड़का लड़की को लेकर भगोरिया हाट से ही भाग जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। इसी तरह अगर युवक, युवती के गालों पर गुलाबी रंग लगा दे और जवाब में लड़की भी उसके गाल पर गुलाबी रंग लगा दे, तो भी यह रिश्ता तय माना जाता है।

मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य

बूंदी, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में फैले मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को दर्रा वन्यजीव अभयारण्य और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस अभ्यारण्य में सरकार अब कूनो अभ्यारण्य की तरह चीतों को बसाने की योजना पर काम कर रही है। इस की स्थापना साल 2004 में दर्रा वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य और जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य को मिलाकर की गई थी। कोटा से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह अभयारण्य रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व के बाद राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह टाइगर रिजर्व चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है, जिसमें कई औषधीय वनस्पति पाई जाती है। यह रिजर्व में बाघ, तेंदुए, जंगली सूअर, लकड़बग्घा, सुस्त भालू, हिरण, भेड़िये, चिंकारा और मृग के अलावा कई पक्षी प्रजातियों का भी घर है।

संचालन पर जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान, गौशाला के ट्रांसफार्मर से बिजली जला रहे दबंग

शिवपुरी में 157 गौशाला, 47 करोड़ खर्च पर अधिकांश खाली

शिवपुरी। जागत गांव हमार

कांग्रेस सरकार ने शिवपुरी जिले में 30 गोशालाएं बनवाई, फिर सत्ता बदली और भाजपा सरकार आई तो जिले में 152 गोशालाएं और मंजूर हो गई। इनमें से कुल 157 गोशालाएं बन चुकी है, लेकिन अधिकांश गोशालाएं संचालित नहीं होने से बंद है। दैनिक भास्कर ने गांवों में बंद गोशालाओं और उनके आसपास लगी जमीनों की छानबीन की तो पता चला कि सैकड़ों बीघा सरकामी जमीन पर अवैध खेती हो रही है। चरनोई और चारागाह की जमीनें सुरक्षित करने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग के पटवारी, आरआई से लेकर अफसरों की है लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा का। उधर, गोवंश सड़कों पर भटक रहा है। पिपरसमां गांव में गोशाला के लिए अलग से ट्रांसफार्मर रखा है। जो लोग चरनोई को जमीन पर खेती कर रहे हैं, वह इसी ट्रांसफार्मर से तार खोचकर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। गोशाला के अंदर लोग अपना अनाज रखकर उपयोग में ले रहे हैं। परिसर में घास उग आई है।

जिन गांवों में गौशालाएं बन चुकी हैं, उसके संचालन के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी तक 62 गौशालाएं संचालन की स्थिति में आ गई हैं। जहां गौशालाएं बनीं हैं, वहां चरनोई और चारागाह की जमीन के बारे में पता कराएंगे। जमीनें अतिक्रमण मुक्त कराकर गौवंश के उपयोग में ली जाएंगी।
रविंद्र कुमार चौधरी, कलेक्टर, शिवपुरी

गोशालाएं बंद, इससे लगी जमीनों पर अवैध खेती

पिपरसमां: 58 बीघा के सर्वे नंबर में गोशाला, आसपास अवैध खेती: शिवपुरी तहसील के पिपरसमां गांव में सर्वे नंबर 106 रकबा बीघा में बनी गोशाला खाली पड़ी है। यह जमीन चारागाह के रूप में दर्ज है। इसी से लगी सर्वे नंबर 108 को 240 बीघा सरकारी जमीन में से आधी से ज्यादा में अवैध खेती है। सर्वे नंबर 105 व 79 की 8 बीघा जमीन पर भी सोली हो रही है।

मोहरा: एक गोशाला खाली, 24 बीघा में अवैध खेती हो रही: कोलारस तहसील के ग्राम मोहरा में सड़क किनारे सर्वे नंबर 534 रकबा 11 बीघा में गोशाला बनी है, लेकिन गोशाला संचालित नहीं हो रही। इसी से लगे सरकारी सर्वे नंबर 1380 रकबा 244 बीघा में से 100 बीघा में अवैध खेती हो रही है। पास के सर्वे नंबर 317 व 1371 और 24 बीघा और जमीन है, जिसमें अवैध खेती की जा रही है।

लुकवासा: 120 बीघा से ज्यादा जमीन पर अतिक्रमण कर खेती की जा रही: कोलारस तहसील के लुकवासा में मंडी के पीछे सरकारी सर्वे नंबर 1779 रकबा 67 बीघा चारागाह के रूप में दर्ज है। इसी में गोशाला बनी हैं। गोशाला तो संचालित है, लेकिन आसपास लगी जमीन पर अवैध खेती हो रही है। इसी से लगे दूसरे सर्वे नंबर 1777 रकबा 126 चौधा चरनोई है। जिसमें से 6-7 बीघा में सरकारी स्कूल, पैक्स गोदाम बना है। लोगों के आवास हैं। 50 प्रतिशत जमीन में अवैध खेती की जा रही है।

भडौता: राजस्व व वनभूमि सहित 1300 बीघा जोतकर अवैध खेती कर रहे: सर्वे नं. 1552 का रकबा 705 बीघा है। जिसमें गौशाला बनी है। इसी में 300 बीघा में अतिक्रमण कर खेती की जा रही है। इसी जमीन पर अमृत सरोवर है जो पर्याप्त नाहीं भरा है। 20 बीच जमीन फिल्टर डासे स्कूल के लिए दी है। वहीं वग विभाग की। हजार बीघा जमीन जोलकर अवैध खेती की जा रही है।

अब पानी की अधिक खपत वाली धान की खेती नाम मात्र की

-भू-जल संकट के लिए खेती को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं

कारखानों और शहरीकरण की वजह से भी बढ़ा भू-जल संकट

भोपाल। जागत गांव हमार

पंजाब और हरियाणा में गिरता भू-जल स्तर भविष्य में खेती के लिए बड़ी समस्या खड़ी करेगा, क्योंकि खेती में सबसे ज्यादा भू-जल का इस्तेमाल होता है। किसानों को पैसा देकर पानी बचाने के लिए दोनों सूबों में धान की खेती को हतोत्साहित भी किया जा रहा है। दोनों की सरकारों के लिए पानी बड़ी चिंता का विषय है। इस बीच आईआईटी-दिल्ली और नासा के हाइड्रोलॉजिकल साइंसेज लैबोरेटरी की एक स्टडी में पता चला है कि पंजाब और हरियाणा ने 2003 से 2020 के बीच 17 वर्षों में 64.6 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल खो दिया है। भूजल की यह मात्रा ओलंपिक आकार के लगभग 25 मिलियन स्विमिंग पूल भर सकती है। यह रिपोर्ट तेजी से घटते संसाधनों पर शहरीकरण के संभावित प्रभाव को रेखांकित कर रही है। हालांकि, इसके लिए सिर्फ खेती या धान जिम्मेदार नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि स्टडी में गुरुग्राम और फरीदाबाद में भू-जल की काफी कमी बताई गई है, जहां पानी की अधिक खपत वाली धान की खेती नाम मात्र की रह गई है। जहां धान की खेती होती है वहां पर हालात फरीदाबाद और गुड़गांव से थोड़े बेहतर हैं। यह दर्शाता है कि फरीदाबाद और गुरुग्राम में अधिकांश जल संसाधन का दोहन शहरी फैलाव के कारण हुआ है। यह स्टडी हाइड्रोजियोलॉजी जर्नल में पब्लिश हुई है।

भू-जल की कमी का असर - शोधकर्ताओं ने देश भर में भू-जल स्तर का विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय भू-जल बोर्ड, साइट निरीक्षण, उपग्रह डेटा और हाइड्रोलॉजिकल मॉडल के डेटा पर भरोसा किया, फिर इन आंकड़ों को क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक मापदंडों के साथ देखा। उसी अवधि में बारिश के पैटर्न में किसी भी बदलाव की जांच करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के डेटा का अध्ययन किया।

इसलिए बढ़ा भू-जल संकट

आंकड़ों से पता चला है कि पंजाब और हरियाणा में 2000 से 2015 तक भू-जल स्तर में 8-10 फीसदी की गिरावट आई है। दोनों राज्यों में, वित्त वर्ष 2004-2005 में कारखानों की वृद्धि दर 69 फीसदी थी और यह वित्त वर्ष 2018-2019 में 170 फीसदी तक पहुंच गई। इसी तरह, 2001 में शहरीकरण की वृद्धि 10 फीसदी थी, और 2011 तक यह 20 फीसदी हो गई। इस दशक (2001 से 2011) के दौरान शहरी आबादी का प्रतिशत 10-20 फीसदी तक बढ़ गया, जो देश भर में शहरी आबादी में सबसे अधिक वृद्धि में से एक है। इसके अलावा, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए भू-जल की मांग में 26 से 228 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार, सरकारी हस्तक्षेप और वर्षा में कोई प्रत्यक्ष गिरावट नहीं होने के बावजूद, भूजल की मांग में तेजी आई है।

यह भी रहे शामिल

आईआईटी-दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर मनबेंद्र सहरिया इस स्टडी में शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा, भू-जल की कमी के प्रभावों में कृषि उत्पादकता में कमी और मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट शामिल है। कृषि-प्रधान राज्य के लिए इसका सामाजिक प्रभाव होगा।

पांच हॉटस्पॉट

स्टडी में भू-जल की सबसे ज्यादा कमी वाले पांच हॉटस्पॉट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। जिसमें धान की खेती वाले पंजाब और हरियाणा सबसे ऊपर हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और केरल का नंबर है। स्टडी में कहा गया है कि कृषि के लिए सिंचाई सभी पांच हॉटस्पॉट में भूजल निष्कर्षण का एक सामान्य कारण था, लेकिन पंजाब और हरियाणा में अन्य संभावित कारणों में उद्योगों का विस्तार, जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण भी शामिल हैं।

छिंदवाड़ा और डिंडोरी जिले के 7-7 गांव बनेंगे आदर्श ग्राम

पीएम जन-मन में 118 पीवीटीजी बहुल गांव बन रहे आदर्श ग्राम

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जन-मन) योजना में प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर और पिछड़े जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के समग्र कल्याण के लिये तेजी से काम जारी है। प्रदेश के 24 जिलों में निवासरत बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजातियां पीवीटीजी में आती हैं। पीएम जन-मन में इन 24 जिलों के 118 पीवीटीजी बहुल गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिये चुना गया है। चयनित आदर्श ग्रामों में सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के अधोसंरचना विकासमूलक कार्यों सहित सभी प्रकार के कल्याण कार्यक्रमों का तेजी से क्रियान्वयन किया जा रहा है। चुने गये 118 आदर्श ग्रामों में से सिवनी जिले का झिंजरई गांव आदर्श ग्राम के रूप में विकसित हो चुका है। यहां सरकार द्वारा सभी योजनाओं को शत-प्रतिशत अमल में लाया गया है। योजना में 23 जिलों के 92 आदर्श ग्रामों में अधोसंरचनात्मक विकास कार्य पूरे हो चुके हैं। 16 जिलों के 48 आदर्श ग्राम में हितग्राहीमूलक काम पूरे होकर लाभार्थियों को दे दिये गये हैं। सात जिलों के 19 आदर्श ग्राम में अधोसंरचनात्मक विकास एवं हितग्राहीमूलक दोनों कार्य पूरे कर लिये गये हैं। पीएम जन-मन योजना में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा कुल 118 पीवीटीजी बहुल गांव को मॉडल विलेज बनाकर इनमें सभी प्रकार की योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन कर यहां आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। योजना में छिंदवाड़ा एवं डिंडोरी जिले में 7-7 एवं कटनी में 6 पीवीटीजी बहुल गांव आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किये जा रहे हैं। अनूपपुर, अशोकनगर, उमरिया, गुना, ग्वालियर, जबलपुर, दतिया, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, मुरैना, रायसेन, विदिशा, शहडोल, शिवपुरी, श्योपुर, सिंगरौली, सिवनी एवं सीधी जिले में 5-5 पीवीटीजी बहुल गांव, आदर्श ग्राम के रूप में तैयार किये जा रहे हैं। इसी क्रम में मैहर जिले के 2 एवं भिंड जिले के एक गांव को भी आदर्श ग्राम बनाया जा रहा है।

कीटों पर बेअसर कीटनाशक, किसानों को कर रहे बीमार

संजय माकवे
वरिष्ठ पत्रकार और सफल कृषक

खेती में कोई फसल ऐसी नहीं, जिस पर कीट का प्रकोप नहीं होता। इसलिए कीटनाशकों का चलन बढ़ता गया है। मगर कीटनाशक कीटों पर नियंत्रण कम, समस्याएं ज्यादा पैदा कर रहे हैं। इनके दुष्प्रभाव से देश में बड़ी तादाद में किसानों को जान गंवानी पड़ती है। फल, सब्जियां और अनाज भी जहरीले होते जा रहे हैं। पशु, पक्षी भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से संबंधित हाल में आया एक अध्ययन डराने वाला है। इसमें कहा गया है कि कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से जहां किसानों में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग बढ़ रहे हैं, वहीं प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर हो रही है।

कीटनाशकों के ज्यादा प्रयोग के चलते किसानों में कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। जिस प्रकार धूम्रपान से कैंसर होता है, उसी प्रकार कुछ कीटनाशकों से भी कैंसर होने का खतरा रहता है। किसानों और कीटनाशकों के अत्यधिक संपर्क में आने वाले अन्य लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। अध्ययन के अनुसार 69 कीटनाशक सीधे तौर पर कैंसर के बढ़ते मामलों से संबद्ध पाए गए हैं। यह अध्ययन अमेरिका में राकी विस्टा विश्वविद्यालय से जुड़े शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किया गया है। पर इसे अमेरिका में होने के कारण खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें जिन मेथोमाइल, मेटोलाक्लोर, एसीफेट 2 व 4 डी जैसे कीटनाशकों का जिक्र है, उनका हमारे देश में खरपतवार और कीटों के खात्मे के लिए खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है।

हमारे देश में कीटनाशकों का बढ़ता इस्तेमाल पहले ही चिंता का विषय है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय की एक रपट के मुताबिक, 1950- 51 में भारत में किसान केवल सात लाख टन रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करते थे, यह आंकड़ा अब 335 लाख टन हो चुका है। एक अन्य रपट के अनुसार 2013 के बाद से भारत में खेती में कीटनाशकों का उपयोग पांच हजार मीट्रिक टन बढ़ा है। देश में बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य की मांग पूरा करने के लिए किसान कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, ताकि पैदावार अधिक हो सके। जैसे-जैसे कीटों और पौधों की बीमारियों की तादाद बढ़ रही है, वैसे-वैसे कीटनाशकों का उपयोग भी बढ़ रहा है।

कीटनाशकों के इस्तेमाल के मामले में पंजाब सबसे आगे है। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के एक अध्ययन में बताया गया है कि देश में सर्वाधिक 1250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कीटनाशक पंजाब में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके बाद 1100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कीटनाशक हरियाणा में उपयोग होते हैं। कीटनाशकों के इस्तेमाल में कपास और धान उपजाने वाला तेलंगाना अब पंजाब और हरियाणा के साथ होड़ कर रहा है, जहां 900 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कीटनाशक छिड़के जा रहे हैं। कीटनाशकों के साथ रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल भी बहुतायत में हो रहा है। देश में हरियाणा में सर्वाधिक 386 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक डाले जा रहे हैं। बिहार में 317 किलोग्राम, पंजाब में 315 किलोग्राम तथा उत्तर प्रदेश में 315 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों के

अनुसार कीटों में कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है, जिससे अब कीटनाशक उतने प्रभावकारी नहीं हो पा रहे हैं। पहले कीटनाशकों की निर्धारित मात्रा के छिड़काव से जो कीट नष्ट हो जाते थे, अब उन पर उनका प्रभाव नहीं हो पा रहा है। इससे किसान का खर्च व्यर्थ जा रहा और खेती की लागत बढ़ रही है। यह सही है कि रासायनिक कीटनाशकों और खाद के इस्तेमाल से फसल उत्पादन बढ़ा है, मगर इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि इसका हमारी जमीन, खेती, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है। कीटनाशकों के कारण हमारी हवा, मिट्टी और पानी में जहर घुल रहा है। अनाज, फल और सब्जियों के जरिए विषैले तत्त्व हमारे शरीर में पहुंच कर हमें बीमार कर रहे हैं।

कीटनाशकों के अधिक इस्तेमाल से जैव विविधता प्रभावित हो रही है। मानव के साथ वन्य जीव, घरेलू पशु और पक्षी भी इसके दुष्प्रभाव झेलने पर मजबूर हैं। अनेक अध्ययनों से जाहिर है कि कीटनाशकों से भूजल प्रदूषित हो रहा है। कीटनाशकों के कारण मधुमक्खियों की संख्या घट रही है। इस वजह से परागण का प्राकृतिक जरिया बाधित हो रहा है, जिससे उत्पादन प्रभावित हो रहा है। सात वर्ष पहले यूनिवर्सिटी आफकैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं ने अपने शोध में चेतावनी दी थी कि मधुमक्खियों के खत्म होने से परागण की प्रक्रिया थम जाएगी और इसका परिणाम पेड़-पौधे घटने तथा मानव जीवन प्रभावित होने के रूप में सामने आएगा।

इस प्रकार, कीटनाशकों का बढ़ता इस्तेमाल हमारे लिए लगातार न जाने कितनी समस्याएं पैदा कर रहा है। अगर हम जल्द नहीं चेते, तो भविष्य में यह समस्या और बढ़ेगी। हमें धीरे-धीरे रासायनिक खेती छोड़ कर प्राकृतिक खेती की ओर लौटना ही होगा। किसानों को खेती में रासायनिक कीटनाशकों की जगह जैविक और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग बढ़ाना होगा। लोगों को स्थानीय और जैविक कृषि उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये उत्पाद कीटनाशक रसायनों के कम संपर्क में होते हैं। हम अगर जैविक कृषि उत्पादों को ज्यादा महत्व देंगे, तो अधिकाधिक किसान ऐसे उत्पादों की खेती की ओर उन्मुख होंगे। इससे रासायनिक कीटनाशकों और खादों का इस्तेमाल घटेगा।

कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि कीटनाशकों के बजाय जैविक तरीके अपनाने से पर्यावरण को नुकसान कम होगा। जैविक कीटनाशकों से नुकसान कम होगा और मित्र कीट बचे रहेंगे। फसल विविधता अपना कर विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करने से कीटों और बीमारियों के फैलाव को नियंत्रित किया जा सकता है। कीटों को खत्म करने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल करने के बजाय ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए, जिससे कीटों के प्राकृतिक शत्रु पनप सकें। जिस गोबर खाद को हमने भुला दिया है, वह इस समस्या का एक बड़ा हल है। गोबर को खाद के रूप में इस्तेमाल करना बंद किया, तो घरों, खेतों में पालतू पशुओं की तादाद घट गई। हमने हजारों-लाखों पशु बेसहारा छोड़ दिए हैं, जो सड़कों पर दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। अगर ये पशु घर के खूंटे से बंधे होते तो प्राकृतिक खाद का जरिया बनते।

हमने अपनी जड़ों से कट कर मुसीबतों को न्योता दिया है। हम नए से जुड़ने की चाहत में पुराने की उपयोगिता को भुला बैठे हैं। उचित यही है अपने मूल की ओर लौट चलें। वतर्मान में प्राकृतिक खेती से जुड़े उपाय ही बेहतर विकल्प हैं, जिन्हें अपनाकर जहां कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है, वहीं एक स्थिर और स्वस्थ कृषि प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ पाना भी मुमकिन है। प्रकृति से तालमेल पर आधारित यह एक ऐसी कृषि प्रणाली होगी, जिसमें न कैंसर का डर होगा और न ही अन्य बीमारियों के चपेट में आने का भय। खेती की लागत घटेगी, किसान खुशहाल होंगे और हमारा पर्यावरण साफ-सुथरा होगा।

अपने स्वान को कैसे प्रशिक्षित करें: एक संपूर्ण मार्गदर्शन

» डॉ. शिवम सिंह मेहरोत्रा
» डॉ. आरके बघेरवाल
» डॉ. हेमंत मेहता
» डॉ. मुकेश शक्य
पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू मध्य प्रदेश

स्वान हमारे जीवन के अनमोल साथी होते हैं। उन्हें सही तरीके से प्रशिक्षित करना न केवल उनके व्यवहार में सुधार लाता है, बल्कि यह उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। लेख में स्वान प्रशिक्षण के कुछ वैज्ञानिक तरीकों और तकनीकों पर चर्चा करेंगे। स्वान को प्रशिक्षित करने के लिए सही मानसिकता अपनाना जरूरी है। अनुसंधान से पता चला है कि सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रशिक्षण में सफलता की संभावना बढ़ती है। स्वान उन मालिकों के साथ बेहतर व्यवहार करते हैं, जो धैर्य और सकारात्मकता के साथ प्रशिक्षित करते हैं।

स्वानों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त समय और स्थान का बहुत मत्व होता है। शांत और कम व्यस्त स्थान पर प्रशिक्षण देना अधिक प्रभावी होता है। अनुसंधान के अनुसार, स्वान ध्यान केंद्रित करने में अधिक सक्षम होते हैं जब उनका वातावरण शांत होता है।

सकारात्मक सुदृढीकरण तकनीक: पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट यानी सकारात्मक सुदृढीकरण स्वान के प्रशिक्षण की एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि में स्वान को अच्छे व्यवहार के लिए इनाम दिया जाता है, जिससे वह उस व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित होता है।

सही आदेश: प्रशिक्षण शुरू करते समय सरल और स्पष्ट आदेशों का उपयोग करें। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि स्वान कम से कम 165 शब्दों को पहचान सकते हैं। जब आप सरल और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वह उन्हें जल्दी समझते हैं।

निरंतरता: स्वान के प्रशिक्षण में निरंतरता बनाए रखना बहुत जरूरी है। शोध के अनुसार, जब स्वान को लगातार सकारात्मक सुदृढ़ीकरण प्रशिक्षण मिलता है, तो वे अधिक तेजी के साथ सीखते हैं।

प्रशिक्षण के चरण

स्वान को प्रशिक्षित करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

बुनियादी आदेश: बुनियादी आदेशों पर ध्यान दें: बैठो: जब स्वान बैठता है, तो उसे इनाम दें। यह स्वान के लिए एक सुरक्षित और सुसंगत संकेत है। **लेटो:** स्वान को लेटने के लिए कहें। इससे उसकी आत्म-नियंत्रण क्षमता में सुधार होता है। **आओ:** जब आप उसे बुलाएं और वह आपके पास आए, तो उसे तुरंत इनाम दें। यह उसे सकारात्मक रूप से संलग्न करता है।

सामाजिककरण

स्वान का सामाजिककरण महत्वपूर्ण है। अनुसंधान से पता चलता है कि जो स्वान अन्य स्वानों और लोगों के साथ सामाजिक रूप से मिलते हैं, वे कम आक्रामक होते हैं और बेहतर सामाजिक व्यवहार करते हैं। नए अनुभवों से स्वान का आत्मविश्वास भी बढ़ता है।

व्यवहार सुधार: यदि स्वान कोई गलत व्यवहार करता है, तो उसे तुरंत समझाएं। एक अध्ययन में पाया गया कि सकारात्मक सुदृढीकरण और सही समय पर फीडबैक देने से स्वानों के व्यवहार में सुधार होता है।

समस्या समाधान: अलगाव की चिंता: कुछ स्वान अकेले रहने पर चिंता महसूस करते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान में यह पाया गया है कि स्वानों को धीरे-धीरे अकेला छोड़ने से उनकी चिंता कम हो सकती है। पहले कुछ मिनटों के लिए छोड़ें और फिर धीरे-धीरे समय बढ़ाएं।

अत्यधिक भौंकना: यदि आपका स्वान अत्यधिक भौंकता है, तो उसे सही समय पर सही व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित करें। अध्ययन बताते हैं कि जब स्वान को शांत रहने पर इनाम मिलता है, तो वे अधिक शांत व्यवहार करना सीखते हैं।

धैर्य और प्यार: प्रशिक्षण के दौरान धैर्य और प्यार बेहद महत्वपूर्ण हैं। अनुसंधान के अनुसार, स्वान अपने मालिकों के मूड को पढ़ सकते हैं। यदि आप सकारात्मक और धैर्यवान हैं, तो आपका स्वान भी बेहतर प्रतिक्रिया देगा। अपने स्वान को प्रशिक्षित करना एक पुरस्कृत प्रक्रिया है, जो आपको और आपके स्वान को एक-दूसरे के साथ और करीबी बनाती है। वैज्ञानिक तकनीकों जैसे सकारात्मक सुदृढीकरण, सही आदेश, और धैर्य के साथ आप अपने स्वान को एक आदर्श साथी बना सकते हैं। एक खुश और प्रशिक्षित स्वान न केवल आपके घर में एक सकारात्मक वातावरण लाता है, बल्कि वह आपके परिवार का एक अनमोल हिस्सा भी बन जाता है। अपने स्वान को प्यार दें, उसे प्रशिक्षित करें, और उसके साथ हर पल का आनंद लें।

जागत गांव हमार, सलाहकार मंडल

1. **प्रो. डा. केआर मौर्य, पूर्व कुलपति,** राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसासमस्तीपुर (बिहार) एवं महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)
ईमेल-kuber.ram@gmail.com, मोबा- 7985680406

2. **प्रो. डा. गैब्रियल लाल, प्रोफेसर,**
आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग सैम हिगिन बॉटम यूनिवर्सिटी आफएग्रीकल्चर, टेक्नालोजी एंड साइंसेज, प्रयागराज, उप्र। ईमेल- gaibriyal.lal @shiats.edu.in, मोबा- 7052657380

3. **डा. वीरेन्द्र कुमार, प्रोफेसर एंड हेड,**
पौध रोग विज्ञान विभाग, डा. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर ढोली, मुजफ्फरपुर बिहार। ईमेल- birendraray@gmail.com
मोबा- 8210231304

4. **डा. नरेश चन्द्र गुप्ता, वैज्ञानिक,** मृदा विज्ञान, कृषि महाविद्यालय बिरसा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची झारखण्ड। ईमेल- ncguptabau@gmail.com, मोबा- 8789708210

5. **डा. देवेंद्र पाटिल, वैज्ञानिक** (शस्य विज्ञान)
कृषि विज्ञान केन्द्र, सीहोर (मध्यप्रदेश)
सेवनिया, इछावर, सिहोर (मप्र)
ईमेल- dpatil889@gmail.com, मोबा- 8827176184

6. **डा. एसके सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर,** एग्री बिजनेस मैनेजमेंटकृषि अर्थशास्त्र विभाग, एकेएस,विश्वविद्यालय, सतना, मप्र
ईमेल- kumar.ashu777@gmail.com, मोबा- 8840014901

7. **डा. बिनीता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर** आनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग एकेएस विश्वविद्यालय, सतना, मप्र
ईमेल- singhvineeta123@gmail.com, मोबा- 8840028144

8. **डा. आरके शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर,** परिजीवी विज्ञान विभाग, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बिहार।
ईमेल- drrksharmabvc@gmail.com, मोबा- 9430202793

9. **डा. दीपक कुमार, सहायक प्राध्यापक,** मृदा एवं जल संरक्षण अभियंत्रिकी विभाग, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, उत्तराखण्ड।
ईमेल- deepak.swce.cot.gbpuat@gmail.com, मोबा- 7817889836

10. **डा. भारती उपाध्याय, विषय वस्तु विशेषज्ञ** (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, पिरौली, समस्तीपुर, बिहार।
ईमेल-bharati.upadhya@rpcau.ac.in, मोबा- 8473947670

11. **डा. रोमा वर्मा,** सब्जी विज्ञान विभाग महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़।
ईमेल- romaverma35371@gmail. com, मोबा- 6267535371

पत्तागोभी से हर साल 70 लाख तक की कमाई

प्रति एकड़ 35 से 40 हजार रुपए खर्च 80 से 100 क्विंटल तक उत्पादन

रायआमला-सोनूरा-बाड़ेगांव के 1500 किसान भी यही फसल ले रहे

पत्तागोभी लगाने के बाद ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, किसान को हर दिन खेत जाना पड़ता है...

मुलताई। जागत गांव हमार

पत्तागोभी से हर साल 70 लाख की कमाई...पढ़कर हो सकता है कि आपको हैरानी हो लेकिन ये सच है। बैतूल जिले में मुलताई से 22 किलोमीटर दूर बिरूल बाजार क्षेत्र के एक युवा किसान भूपेश सोनी ने 10 एकड़ जमीन में सिर्फ पत्तागोभी उगाकर ऐसा कर दिखाया है। करीब 40 साल पहले सोयाबीन में घाटा हुआ तो भूपेश सोनी के पिता ने सब्जी की खेती शुरू की। इसे भूपेश ने आगे बढ़ाया। पहली बार में ही मुनाफा हुआ, तब से लगातार पत्तागोभी की फसल ही उगा रहे हैं। उन्हें देखकर आसपास बसे रायआमला, सोनूरा और बाड़ेगांव के करीब 1500 किसान भी अब यही फसल ले रहे हैं। यही कारण है कि बिरूल बाजार प्रदेश में सबसे ज्यादा पत्तागोभी उत्पादन के लिए जाना जाता है। **जागत गांव हमार** अपने इस अंक में बता रहा है कि भूपेश सोनी के बारे में...।

भूपेश बताते हैं, 'करीब 40 साल पहले की बात है। मेरी उम्र दो साल रही होगी। दादाजी कलीराम सोनी खेत में सोयाबीन उगाते थे। उसमें मुनाफा कम और लागत ज्यादा हो रही थी। किसी ने उन्हें पत्तागोभी की खेती करने की सलाह दी। रिस्क लेकर दादाजी ने पत्तागोभी लगाया। इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिता हेमराज सोनी और मैं खुद इसे आगे बढ़ा रहा हूं। 10 एकड़ जमीन पर सिर्फ और सिर्फ पत्तागोभी की खेती करते हैं। यह फसल साल में तीन बार ली जा सकती है, क्योंकि यह चार महीने की है। एक महीने में रोप कर तैयार किया जाता है। अगले तीन महीने में फसल तैयार हो जाती है। इसके लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता होना चाहिए। हर सात दिन में पानी देना पड़ता है।

एक सीजन में प्रति एकड़ 35 से 40 हजार रु. खर्च

भूपेश का कहना है कि पत्तागोभी की खेती में एक सीजन में प्रति एकड़ 35 से 40 हजार रुपए खर्च आता है। एक एकड़ में 80 से 100 क्विंटल उत्पादन होता है। बाजार में यह तीन लाख रुपए में बिक जाती है। सीजन में प्रति एकड़ करीब ढाई लाख रुपए का मुनाफा मिल जाता है। इस तरह एक सीजन में 10 एकड़ में करीब 25 लाख और साल में करीब 70 लाख से ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। भूपेश ने बताया कि पत्तागोभी लगाने के बाद ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। किसान को हर दिन खेत जाना पड़ता है। स्प्रे, निराई-गुड़ाई, खाद, पानी का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे ज्यादा महंगी मजदूरी पड़ती है।

पत्तागोभी की फसल में रिस्क भी ज्यादा

कीट और इल्लियों का प्रकोप: पत्तागोभी में कीटों और इल्लियों का प्रकोप सबसे ज्यादा रहता है। इससे बचने के लिए पौधे रोपने के बाद से ही लगातार निराई-गुढ़ाई करें। समय-समय पर कीटनाशक का छिड़काव करें।

फसल में देरी: यदि फसल समय पर तैयार नहीं होती तो बाजार में दाम नहीं मिल पाता।

फूल में कीड़े लगना: तैयार फसल में सबसे ज्यादा माहू के प्रकोप की आशंका रहती है। कीड़े लगने पर फूल खराब हो जाता है।

जैविक खाद का उपयोग कम: इस फसल में जैविक खाद का उपयोग बहुत कम होता है। रासायनिक खादों पर ही किसानों को निर्भर रहना पड़ता है।

रोजाना 100 ट्रक पत्तागोभी बाहर भेजी जाती है...

भूपेश ने कहा, बिरुल बाजार क्षेत्र से रोजाना करीब 100 ट्रक पत्ता गोभी दूसरे राज्यों में भेजी जाती है। यहां 1500 किसानों ने 500 एकड़ में पत्ता गोभी उगाई है। इससे करीब 10 हजार टन उत्पादन का अनुमान है। यहां से जयपुर, ओडिशा, दिल्ली, कोलकाता, नागपुर, रायपुर, पटना, इलाहाबाद, चेन्नई, मुंबई तक पत्तागोभी भेजी जाती है। दरअसल, यहां की गोभी का फूल कड़क रहता है, जो ज्यादा दिन तक खराब नहीं होता।

अब जानिए, कैसे उगाएं पत्तागोभी

मुलताई के बिरुल बाजार क्षेत्र में चंदोरा डैम होने के कारण मिट्टी में नमी है। पत्तागोभी लगाने के लिए नमी वाली काली मिट्टी बेहतर होती है। एक एकड़ जमीन में 700 से 800 पौधे लगाए जा सकते हैं।

पत्तागोभी की फसल के लिए एक एकड़ क्षेत्र में 20 बाय 20 की जगह में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर बीज डाले जाते हैं। इसे बाफा कहते हैं। करीब एक महीने बाद पौधे तैयार हो जाते हैं, जिन्हें रोपा कहते हैं।

इसके बाद खेत की जुताई करके क्यारियां बनाते हैं। करीब आधे-आधे फीट की दूरी पर इन पौधों को लगा दिया जाता है। दूरी इतनी रखते हैं कि फूल बनने के बाद उसे फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। तीन महीने में फसल तैयार हो जाती है। इसके बाद इसे काटा जाता है।

अब खेती-बाड़ी में भी उतरा रोबोट...इन 7 तरह के काम में कर सकते हैं इस्तेमाल

भोपाल। जागत गांव हमार

अब रोबोट यत्र-तत्र-सर्वत्र हैं। कोई जगह बाकी नहीं जहां रोबोट अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा रहे। यहां तक कि खेती में भी उनका महत्व और काम बढ़ गया है। बस फर्क यही है कि जो किसान रोबोट का महत्व समझते हैं, जो किसान इसका खर्च वहन कर सकते हैं, वे ही रोबोट का सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इसका प्रचलन विदेशों में अधिक है, लेकिन भारत में भी अब इसकी छाप दिखाई देने लगी है। दरअसल, खेती में रोबोट वहां अधिक दिखाई दे रहे हैं जहां इस काम में रिस्क है। जहां इंसानों के पहुंचने में खतरा है, वहां रोबोट आसानी से खेती के काम को अंजाम दे रहे हैं। वैसे कृषि काम में भी रोबोट का इस्तेमाल लाभदायक है जिनका सेहत पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कीटनाशक का छिड़काव आदि। रोबोट खेती में उपज बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं, साथ ही लागत घटाने में भी इनका बड़ा रोल है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मोटे बीजों के लिए प्रेसिजन प्लांटर पर बड़ा काम किया है जिससे कम समय में खेतों में अधिक बीजों की बुवाई की जा सकती है। जैसा कि आपको पता है, खेती में अधिक

उपज पाने के लिए निराई-गुड़ाई का काम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। इसी तरह के और भी कई काम हैं जिनमें रोबोट का इस्तेमाल क्रांतिकारी साबित हो रहा है। आइए ऐसे काम के बारे में जान लेते हैं।

इन 7 कामों इस्तेमाल

मिट्टी नमूना को जुटाना- इसके लिए स्मार्टकोर नाम के रोबोट का प्रयोग कर सकते हैं जो ऑटोमेटिक ढंग से मिट्टी के सैंपल लेता है।

बीजों की बुवाई- इस काम के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने रोबोट तैयार किया है जो खेतों में आसानी से बीज बुवाई करता है।

पेड़ लगाना- किसी पेड़ को काटे बिना एक जगह से दूसरी जगह पर लगाने के लिए ट्री रोवर नाम के रोबोट का प्रयोग किया जा रहा है।

निराई-गुड़ाई- खेत में निराई-गुड़ाई के काम के लिए इवो नाम का रोबोट बनाया गया है।

छंटाई- अंगूर के बागों की छंटाई के लिए कारगर रोबोट तैयार किया गया है।

फसल की कटाई- इसके लिए ऑक्टेनियन रोबोट बनाया गया है जो विशेष रूप से स्ट्रॉबेरी तोड़ने में काम आता है।

मुर्गी पालन- मुर्गी फार्म में पोल्ट्री की देखभाल के लिए स्वैगबॉट नाम का रोबोट बनाया गया है।

मप्र देश का अकेला ऐसा राज्य है जिसे मिला है टाइगर, चीता, लेपर्ड, वुल्फ, वल्चर स्टेट का दर्जा

मप्र में जंगलों लाया जाएगा किंग कोबरा दावा-एशिया का सबसे खतरनाक सांप

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के जंगलों में अब एशिया का सबसे खतरनाक जानवर लाने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इस योजना पर काम कर रही है। योजना तैयार होते ही इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही यह परियोजना राज्य सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश की वाइल्ड लाइफ काफी रिच मानी जाती है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एमपी देश का अकेला ऐसा राज्य है जिसे टाइगर, चीता, लेपर्ड, वुल्फ, वल्चर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। अब इस वाइल्ड लाइफ का हिस्सा किंग कोबरा भी होगा।

वन्य जीव बोर्ड की बैठक में सीएम मोहन यादव ने दिया निर्देश- मध्य प्रदेश के जंगलों में किंग कोबरा को बसाने की पूरी परियोजना वन विभाग तैयार कर रहा है। सीएम मोहन यादव ने वन्य जीव बोर्ड की बैठक में इस संदर्भ के निर्देश भी दिए हैं।

दुनिया का सबसे खूंखार जानवर है किंग कोबरा

बता दें कि दुनिया के सबसे खूंखार जानवर के रूप में जाना जाने वाला किंग कोबरा 18-20 फीट तक लंबा हो सकता है। मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्रों, पश्चिमी-पूर्वी घाट में रहने वाला किंग कोबरा भारत का आधिकारिक सरीसृप माना जाता है।

विलुप्त हो चुके कई जानवरों को एमपी में फिर से बसाने सीएम के निर्देश

दरअसल किंग कोबरा को मप्र के जंगलों में लाने संबंधी परियोजना एमपी सीएम डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर शुरू की गई है। सीएम ने किंग कोबरा के साथ ही विलुप्त हो चुके कई जानवरों को एमपी में फिर से बसाने के निर्देश दिए थे।

अंडे देने के लिए पेड़ों पर घोंसला बनाता है

नागराज कहलाने वाला किंग कोबरा दूसरे सांपों का शिकार करता है। वहीं ये अकेला ऐसा जानवर है, जो अंडे देने के लिए पेड़ों पर घोंसला बनाता है। बता दें कि किंग कोबरा को देश के कई हिस्सों में भगवान शिव के गले में लिपटे नाग के रूप में पूजा जाता है। वहीं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट इसे एशिया का सबसे खतरनाक सांप मानते हैं। इसके बाद भी ये पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसीलिए इसकी आबादी को सुरक्षित रखना काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में किंग कोबरा के संरक्षण के लिए जन जागरुकता और मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए भी आगे आना जरूरी है।

गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है

गौरतलब है कि एशिया के सबसे खतरनाक जानवरों में शामिल किंग कोबरा एमपी के पड़ोसी राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसलिए उम्मीद की जाती है कि वह मध्य प्रदेश के जंगलों में भी होगा। लेकिन ढूंढने पर भी वन विभाग को किंग कोबरा के एमपी में होने के फिलहाल कोई सबूत नहीं मिले हैं।

किंग कोबरा के बारे में कुछ रोचक फैक्ट

- सनातन धर्म में भगवान शिव के गले में लिपटे सांप का नाम वासुकी है। माना जाता है कि वासुकी एक हिमालयन किंग कोबरा ही है।
- पौराणिक कथाओं में वासुकी को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त माना गया है। कहा जाता है उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही वासुकी को भगवान शिव ने आभूषण के रूप में अपनी गरदन पर धारण किया और उन्हें नागलोक का राजा घोषित किया।
- वासुकी यानी किंग कोबरा को नागों का, सांपों राजा भी कहा जाता है।
- यह दुनिया का सबसे लंबा विषधर सांप है।
- एशिया के सबसे खतरनाक सांपों में गिने जाने वाले किंग कोबरा को दुनिया का सबसे स्मार्ट सांप माना जाता है।
- किंग कोबरा बेहद फुर्तीला होता है और अपने विशालकाय आकार के बावजूद तेजी से चल सकता है।
- किंग कोबरा भारत के जंगलों से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर फिलीपींस तक में पाए जाते हैं।
- किंग कोबरा अन्य सांपों को खाता है और अजगर जैसे बड़े सांपों पर भी हमला कर देता है।

जानिए पिछली बार की गणना कितने पशु घटे और बढ़े थे

शुरू हो गई पशुओं की गणना, इस बार ऐप का प्रयोग और छुट्टा जनवरों की भी गिनती

भोपाल। जागत गांव हमार

पशुगणना की तरह से हर पांच साल बाद पशुगणना भी कराई जाती है। इसी से पता चलता है कि देश में गाय-भैंस और भेड़-बकरियों की संख्या घट रही है या बढ़ रही है। अच्छी बात ये है कि इस बार की 21वीं पशुगणना 2024-25 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। इस बार की पशुगणना में कुछ चीजें पहली बार हो रही हैं। जैसे पशुगणना इस बार मोबाइल ऐप से हो रही है। दूसरा ये कि इस बार की पशुगणना में छुट्टा जानवर जैसे गाय और कुत्तों को भी शामिल किया गया है। लेकिन 20वीं पशुगणना 2019 के दौरान गाय-भैंस और भेड़-बकरियों की संख्या कितनी थी।

किन पशुओं की संख्या लगातार घट रही थी। किसी पशु की कोई एक खास नस्ल खतरे में थी। अगर कोई नस्ल बढ़ रही थी तो उसकी संख्या क्या थी इस बारे में सभी आंकड़ों के बारे में हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। क्योंकि जिन पशुओं की नस्लों पर खतरा था उन पर और ज्यादा काम करने की जरूरत होगी।

जानें क्या कहते हैं 20वीं पशुगणना के आंकड़े - 2019 की पशुगणना के मुताबिक देश में पशुधन (लाइव स्टॉक) की कुल आबादी 53.61 करोड़ है। जो पशुधन पशुगणना, 2012 की तुलना में 4.8 फीसद की वृद्धि दिखाती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल पशुधन आबादी 50.14 करोड़ और 2.2 करोड़ है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 95.78 फीसद और शहरी क्षेत्रों में 4.22 फीसद है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल पशुधन आबादी में 4.56 फीसद की वृद्धि हुई थी और शहरी क्षेत्रों में यह वृद्धि 11.19 फीसद थी। पिछली पशुगणना की तुलना में कुल स्वदेशी मवेशियों की आबादी में 6 फीसद की गिरावट आई थी। हालांकि, 2012-2019 के दौरान स्वदेशी मवेशियों की आबादी में गिरावट की गति 2007-12 की तुलना में 9 फीसद से बहुत कम थी।

पिछली पशुगणना की तुलना में 1.1 फीसद की वृद्धि

- 2019 में कुल गोजातीय आबादी (मवेशी, भैंस, मिथुन और याक) 30.4 करोड़ थे, जो पिछली पशुगणना की तुलना में 1.3 फीसद ज्यादा थी।
- 2019 में देश में मवेशियों की कुल संख्या 19.3 करोड़ है, जो पिछली पशुगणना की तुलना में 1.3 फीसद की वृद्धि दिखाती है।
- देश में भैंसों की कुल संख्या 11 करोड़ थी, जो पिछली पशुगणना की तुलना में लगभग 1.1 फीसद की वृद्धि दिखाती है।
- गायों और भैंसों में दुधारू पशुओं (दूध न देने वाले और सूखे) की कुल संख्या 12.60 करोड़ थी, जो पिछली पशुगणना की तुलना में 6.0 फीसद की वृद्धि दिखाती है।
- 2019 में देश में बकरियों की आबादी 15 करोड़ थी, जो पिछली पशुगणना की तुलना में 10.1 फीसद की वृद्धि दिखाती है।
- 2019 में देश में भेड़ों की कुल संख्या 7.5 करोड़ थी, जो पिछली पशुगणना की तुलना में 14.1 फीसद ज्यादा है।
- वर्तमान पशुगणना में देश में सूअरों की कुल संख्या 90 लाख थी, जो पिछली पशुगणना की तुलना में 12.03 फीसद कम है।
- देश में घोड़ों और टट्टुओं की कुल संख्या 2019 में 3.4 लाख थी, जो पिछली पशुगणना की तुलना में 45.2 फीसद कम है।
- देश में खच्चरों की कुल आबादी 2019 में 10000 थी, जो पिछली पशुगणना की तुलना में 57.1 फीसद कम है।
- देश में गधों की कुल आबादी 2019 में 1.2 लाख थी, जो पिछली पशुगणना की तुलना में 61.2 फीसद कम है।
- देश में ऊंटों की कुल आबादी 2019 में 2.5 लाख थी, जो पिछली पशुगणना की तुलना में 37.1 फीसद कम है।
- देश में कुल मुर्गीपालन 2019 में 85 करोड़ थी, जो पिछली पशुगणना की तुलना में 16.8 फीसद अधिक है।
- देश में कुल बैकयार्ड पोल्ट्री 2019 में 32 करोड़ थी, जो पिछली पशुगणना की तुलना में 45.8 फीसद अधिक है।
- देश में कुल वाणिज्यिक पोल्ट्री 2019 में 53 करोड़ थी, जो पिछली पशुगणना की तुलना में 4.5 फीसद अधिक है।

तीन पक्षी पालकर कम लागत में पाएं अच्छा मुनाफा

तीन पक्षी पालकर कम लागत में पाएं अच्छा मुनाफा

भोपाल। जागत गांव हमार

खेती-किसानी के अलावा किसान पशुपालन और पक्षीपालन से भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। आजकल पढ़े लिखे लोग नौकरी छोड़कर भी पशुपालन और खेती-किसानी की तरफ रुख कर रहे हैं। वहीं, सरकार भी लोगों को प्रोत्साहित और आर्थिक मदद (सब्सिडी) के लिए कई तरह की स्कीम चला रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खेती-किसानी और पशुपालन को अपनाएं।

पशुपालन और पक्षीपालन में होता है डबल मुनाफा- अगर आप पशुपालन या पक्षीपालन करते हैं तो आपको एस साथ डबल मुनाफा होगा। यदि आप पक्षी पालते हैं तो इसके मांस के साथ-साथ इसके अंडे भी आसानी से बेच सकते हैं। इसमें मुर्गी, बत्तख और बटेर पालना अच्छा ऑप्शन हो सकता है।

मुर्गी पालन का तरीका और कमाई- भारत में सबसे ज्यादा पक्षी पालन में मुर्गी पालन किया जाता है। मुर्गी पालन का बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको लाइसेंस लेना होता है। इस विषय में आप अपने नजदीकी पशु विशेषज्ञों से जानकारी ले सकते हैं। मुर्गी पालन के लिए आपके पास काफी साफ-सुथरी जगह होनी चाहिए। उनके खाने के लिए विटामिन और प्रोटीन से भरपूर आहार देना होता है। इसके अलावा आप पक्षियों को अनाज, दाने और फल भी खिला सकते हैं। करीब 16-18 हफ्तों में मुर्गियां अंडे देने लगती हैं। इन अंडों को आप बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा लोग मीट के लिए भी मुर्गी खरीदते हैं।

बत्तख पालन का तरीका और कमाई

बत्तख पालन करने के लिए आपको सबसे पहले आपने आस-पास तालाब या कं ीट वाले वाटर टैंक बनवाने होंगे। इसके अलावा आप तालाब, पोखर या फिर नालियां खुदवाकर भी बत्तख पाल सकते हैं। गीला चारा के साथ पानी वाले कीड़े मकोड़े, चावल, मक्का, चोकर और घोंघे मछलियां बत्तख को काफी पसंद है। एक साल में एक बत्तख 300 अंडे देती है।

बटेर पालन का तरीका और कमाई

बटेर को पालने के लिए आपको फर्श में लकड़ी का बुरादा या धान के छिलके बिछाने होंगे, बटेर को खाने में स्वीट कॉर्न, चावल और मिलेट्स पसंद होते हैं। बटेर पालन से आप लगभग 45 दिनों में ही अंडे प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, सर्दियों में बटेर के मांस की डिमांड भी रहती है।

पक्षी पालन के लिए इन बातों का ध्यान रखें

- नियमित रूप से पक्षी के वेटरनरी जांच करवाना चाहिए।
- बीमार होते ही तुरंत इलाज करवाना चाहिए।
- सुरक्षा का ध्यान रखें, पिंजरे को ऐसी जगह पर रखें जहां अन्य पालतू जानवर, जैसे कि बिल्ली या कुत्ता ना पहुंच सके।
- पंख कटवाने या नाखून ट्रिम करने जैसी प्रक्रियाओं में सावधानी बरतें।

सब्जियों की फसल को इन रोगों से बचाएं किसान, अपनाएं ये आसान टिप्स

सब्जियों को रोगों से बचाएं किसान, अपनाएं ये आसान टिप्स

भोपाल। जागत गांव हमार

बागवानी किसानों के लिए कमाई का एक अच्छा साधन है। लेकिन बागवानी में कमाई के साथ कई चुनौतियां भी है, जिनसे निपटने के लिए किसानों को हमेशा जागरूक रहना चाहिए। सब्जी की फसलों में लगने वाले कुछ कीट और रोग , जो फसल को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं और फसल को बर्बाद कर देते हैं। जैसे-

तना और फल छेदक रोग- तना और फ्ल छेदक सब्जियों व फलों के अंदर घुसकर पौधे और फसल को बर्बाद कर देते हैं। इससे बचाव के लिए कीट लगी फलियों व सब्जियों को एकत्रित कर जला देना चाहिए। इसके अलावा खेत में लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहिए। लाइट ट्रैप में कीटों को आग या बल्ब की तेज रोशनी की तरफ आकर्षित किया जाता है और उनका निपटान किया जाता है। इसके अलावा फसल में साइपरमेथ्रीन 40 प्रतिशत ईसी। को प्रति लीटर पानी 1.5 मिली मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।

सफेद मक्खी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाती है। यह शिशु और वयस्क दोनों ही अवस्थाओं में पत्तियों का रस चूसने का काम करती है। इस मक्खी से फसल में वायरस भी फैल सकता है। सफेद मक्खी से फसल के बचाव के लिए सुनिश्चित करें कि खेत में खरपतवार न हो, इसके अलावा प्रति तीन लीटर पानी में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत एसएल की 1 मिली मात्रा मिलाकर छिड़काव करें। या पाइरिप्रोक्सीफेन 40 प्रतिशत ईसी का प्रति लीटर पानी में 1।5 मिली घोल तैयार कर छिड़काव करें।

फल सड़न

फल सड़न रोग होने पर पौधे की पत्तियों में धब्बे बन जाते हैं। यह रोग जमीन से सटे फलों के हिस्सों पर ज्यादा हमला करता है। इसके प्रबंधन के लिए कॉपर आक्सीक्लोराईड 50 प्रतिशत घुलनशील पाउडर का 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से या कार्बेन्डाजीम 50 प्रतिशत घुलनशील पाउडर का प्रति लीटर पानी में 1 ग्राम का घोल तैयार कर छिड़काव करना चाहिए।

उखड़ा रोग

उखड़ा रोग में पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जिसके बाद पौधा सूखने लग जाता है। इसके प्रबंधन के लिए रोग से प्रभावित फसल पर कार्बेन्डाजीम 50 प्रतिशत घुलनशील चूर्ण का प्रति लीटर पानी में 1 ग्राम मिला घोल या कासुगामाइसिन 5 प्रतिशत और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45 प्रतिशत घुलनशील पाउडर का प्रति लीटर पानी में 4.5 ग्राम मिलाकर तैयार किया गया घोल मिट्टी पर छिड़कना चाहिए।

केले की फसल को बर्बाद कर देता है बनाना बंची टॉप रोग, जानिए इसके लक्षण और प्रबंधन

भोपाल। जागत गांव हमार

बनाना बंची टॉप रोग (बीबीटीडी) इसे कई नामों से जानते हैं, जैसे शीर्ष गुच्छ रोग या बांझपन भारतवर्ष में केले की खेती करने वाले सभी क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण रोग है। इस रोग की वजह से प्रभावित पौधों में शत् प्रतिशत नुकसान होता है।

बनाना बंची टॉप रोग के प्रमुख कारण- बनाना बंची टॉप रोग का प्राथमिक कारण बनाना बंची टॉप वायरस है। यह वायरस एक एकल-फंसे डीएनए वायरस है, जो केले के पौधे की संवहनी प्रणाली को संक्रमित करता है, जिससे कई प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं जो पौधे की वृद्धि और उत्पादकता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। वायरस मुख्य रूप से केले में लगने वाले एफ्डि द्वारा फैलता है, जो संक्रमित पौधों को खाता है और फिर बाद में भोजन के दौरान वायरस को स्वस्थ पौधों तक पहुंचाता है।

बनाना बंची टॉप रोग के लक्षण- बनाना बंची टॉप रोग के सबसे विशिष्ट लक्षणों में से एक पत्तियों का गुच्छेदार शीर्ष दिखना है। संक्रमित पौधों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, पत्तियां छोटी और अधिक सीधी हो जाती हैं, जिससे पौधा गुच्छेदार और असामान्य दिखने लगता है। संक्रमित पत्तियों में अक्सर पीलापन, धब्बे या क्लोरोसिस दिखाई देता है, जो पौधे की संवहनी प्रणाली के विघटन और खराब पोषक तत्व परिवहन का परिणाम है। प्रभावित पत्तियों में विभिन्न विकृतियां दिखाई दे सकती है, जिनमें मुड़ना, मुड़ना और पीली धारियों या छल्लों का विकास शामिल है। बनाना बंची टॉप रोग स्वस्थ फलों के उत्पादन को काफी कम कर देता है। संक्रमित पौधे-छोटे और विकृत फल पैदा कर सकते हैं, जिससे वे उपभोग या बिक्री के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। गंभीर मामलों में, वायरस प्रभावित पौधों में परिगलन या मृत्यु का कारण बनता है, जिससे फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है।

बनाना बंची टॉप रोग को कैसे रोकें

एफ्डि नियंत्रण| बनाना बंची टॉप रोग के प्रबंधन में केले एफ्डि की जनसंख्या को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। इसे कीटनाशकों, जैविक नियंत्रण विधियों और खरपतवार-मुक्त परिवेश को बनाए रखने के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। एफ्डि-प्रतिरोधी केले की किस्में भी विकसित की जा रही हैं। स्वस्थ व रोगी पौधों पर कीटनाशक दवा यथा इमीडैक्लोप्रीड 1मिलीलीटर दवा प्रति 2 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, जिससे रोगवाहक कीड़े मर जाते हैं और रोग प्रसार पर रोक लग जाती है। वायरस रोग निदान के लिये कीटनाशक दवा का उपयोग आसपास के सभी बगीचे वालों को मिलकर एक साथ, एक ही दिन करना चाहिए जिससे कीड़े आसपास के बगीचों में न भाग सकें और वे पूरी तरह से नष्ट किया जा सकें वरना रोग प्रकोप को फैलने से नहीं रोका जा सकता है।

संक्रमित पौधों को नष्ट करना| वायरस को स्वस्थ पौधों में फैलने से रोकने के लिए संक्रमित केले के पौधों को तुरंत हटा देना चाहिए और नष्ट कर देना चाहिए। न केवल संक्रमित पौधे को हटाना आवश्यक है, बल्कि आस-पास के किसी भी सकर या पौधे को भी हटाना आवश्यक है, जिसमें वायरस हो सकता है।

प्रतिरोधी किस्में| शोधकर्ता बनाना बंची टॉप रोग (बीबीटीवी) प्रतिरोधी केले की किस्में विकसित करने पर काम कर रहे हैं। ये प्रतिरोधी किस्में प्रभावित क्षेत्रों में बीमारी के प्रभाव को काफी कम कर सकती हैं।

कम समय में ज्यादा फायदे के लिए करें शलजम की खेती

भोपाल। शलजम एक ऐसी सब्जी है जो बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है, जिससे किसान एक सीजन में कई बार इसकी फसल ले सकते हैं। शलजम की खेती किसानों के लिए कम समय में अधिक मुनाफा देने का एक अच्छा विकल्प बन गई है।

शलजम की किस्में- मानक शलजम, बेबी शलजम, पर्पल-टॉप शलजम, गोल्डन शलजम, जापानी शलजम, चारा शलजम।

कैसी हो जलवायु और मिट्टी- शलजम को विभिन्न जलवायु में आसानी से उगाए जा सकते हैं, लेकिन वे ठंडे मौसम में अच्छे से पनपते हैं। अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी आदर्श होती है। शलजम एक विस्तृत पीएच रेंज को सहन कर सकते हैं लेकिन तटस्थ मिट्टी की तुलना में थोड़ी अम्लीय मिट्टी को पसंद करते हैं। शलजम को प्रतिदिन कम से कम 6 घंटे सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है।

खेत की तैयारी| रोपण क्षेत्र को खरपतवार और मलबे से साफ़ करें। मिट्टी को लगभग 6-8 इंच की गहराई तक जुताई करें। मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए खाद जैसे कार्बनिक पदार्थ को शामिल करें।

बुवाई| शलजम के बीज सीधे तैयार मिट्टी में बोयें। गहराई लगभग 1/4 इंच से 1/2 इंच होनी चाहिए। 12-18 इंच की पंक्तियों में बीज को लगभग 2 इंच की दूरी पर रखें। जैसे-जैसे अंकुर बढ़ते हैं, उन्हें पर्याप्त दूरी प्रदान करने के लिए पतला करें।

सिंचाई| मिट्टी को लगातार नम रखें लेकिन जलभराव न होने दें। शलजम को कड़वा होने से बचाने के लिए सूखे के दौरान पानी देना महत्वपूर्ण है।

खाद और उर्वरक| बोवनी करते समय या मिट्टी परीक्षण के निर्देशानुसार संतुलित उर्वरक का उपयोग करें। अतिरिक्त नाइट्रोजन से बचें, क्योंकि इससे पत्ते हरे-भरे और जड़ें छोटी हो सकती हैं।

कीट एवं रोग प्रबंधन| एफिड्स, बीटल और पत्तागोभी कीड़े जैसे सामान्य कीटों की निगरानी करें। क्लबरूट जैसी बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए फसल चक्र अपनाएं। युवा पौधों को कीटों से बचाने के लिए पंक्ति आवरण का उपयोग करें। अत्यधिक पानी देने से सावधान रहें, क्योंकि इससे बीमारियां हो सकती हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने योजना को चलाने के लिए सभी दिशा-निर्देश जारी किए

नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए 1261 करोड़ रुपए मंजूर देश के 14500 स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा लाभ

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम 'नमो ड्रोन दीदी' को मंजूरी दी है, जिसमें 1261 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस योजना के तहत किसानों को किराये की सेवाएं देने के लिए 2024-25 से 2025-26 की अवधि के दौरान 14,500 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन दिया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने इस योजना को चलाने के लिए सभी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वहीं, विभाग ने सभी पक्षकारों से अपील की है कि वे इन दिशा-निर्देशों का इस्तेमाल करें, ताकि 'नमो ड्रोन दीदी' योजना सुचारू रूप से चल सके। जानिए दिशा-निर्देशों में क्या कहा गया है।

80 प्रतिशत सब्सिडी देगी सरकार- यह योजना केंद्रीय स्तर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उर्वरक विभाग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति के निर्देशों के अनुसार चलेगी। दिशा-निर्देशों के मुताबिक, महिला स्वयं सहायता समूहों को पैकेज के रूप में ड्रोन की खरीद के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम 8 लाख रुपए) सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, स्वयं सहायता समूहों और स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर स्तरीय संघों को कुल लागत में से सब्सिडी हटाकर शेष राशि पर लोन दिया जाएगा, जिसमें केंद्र की ओर से 3 प्रतिशत ब्याज सहायता मिलेगी। ये बैंक और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्य कार्यक्रमों या योजनाओं से लोन ले सकेंगे।

सर्विस के साथ पैकेज में मिलेगा ड्रोन सेट

योजना में सिर्फ ड्रोन अकेला नहीं, बल्कि पैकेज के रूप में ड्रोन दिया जाएगा, जिसमें लिक्विड खादों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए स्प्रे सिस्टम के साथ बेसिक ड्रोन, ड्रोन को रखने का बॉक्स, बैटरी सेट, नीचे की ओर फोकस कैमरा, डबल चैनल वाला फास्ट बैटरी चार्जर, बैटरी चार्जर हब, एनीमो मीटर, पीएच मीटर और सभी चीजों पर एक साल की ऑनसाइट वारंटी शामिल होगी। पैकेज में चार एक्स्ट्रा बैटरी सेट, एक अतिरिक्त प्रोपेलर सेट (हर सेट में छह प्रोपेलर होते हैं), नोजल सेट, डुअल चैनल फास्ट बैटरी चार्जर, बैटरी चार्जर हब, ड्रोन पायलट और ड्रोन सहायक के लिए 15 दिन की ट्रेनिंग, एक साल का बीमा, दो साल का वार्षिक रखरखाव कांट्रेक्ट और लागू जीएसटी भी शामिल है। बैटरी के एक्स्ट्रा सेट से ड्रोन लगातार उड़ाया जा सकेगा। एक दिन में ड्रोन से आसानी से 20 एकड़ खेत में छिड़काव किया जा सकेगा।

ड्रोन पायलट को 15 दिन की मिलेगी ट्रेनिंग

योजना के पैकेज के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों में से एक महिला को 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए चुना जाएगा। इस ड्रोन पायलट ट्रेनिंग में पोषक तत्व, कीटनाशक के कम प्रयोग करने जैसी बातों के बारे में जानकारी दी जाएगी। बिजली के सामान की मरम्मत, फिटिंग और यांत्रिक कार्यों में रुचि रखने वाले स्वयं सहायता समूह के अन्य सदस्यों को ड्रोन सहायक के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन निर्माता इसे चलाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार ड्रोन की आपूर्ति के साथ-साथ ट्रेनिंग भी एक पैकेज के रूप में देंगे। योजना के बारे में तमाम जानकारी जैसे ड्रोन का वितरण, निगरानी, फंड बांटने जैसी तमाम सुवि?धाएं और ड्रोन पोर्टल पर उपलब्ध होगी। पोर्टल हर ड्रोन के ऑपरेशन को ट्रैक करेगा और ड्रोन के उपयोग पर लाइव अपडेट देगा।

श्योपुर में 13 साल चंबल सफारी शुरू होने का आज भी इंतजार

पड़ोसी जिले में पर्यटन व्यवसाय कर रही चंबल सफारी

श्योपुर। जागत गांव हमार

पड़ोसी जिले मुरैना में बारिश का सीजन समाप्त होने के बाद चंबल सफारी शुरू कर दी गई है। देवरी गेम रेंज ऑफिसर रिंकी आर्य ने दशहरा के अवसर पर सफारी का फीता काट कर शुभारंभ किया। इधर, श्योपुर जिले की बात करें तो यहां 13 साल पहले (18 नवंबर 2011 को) तत्कालीन वन मंत्री ने इसका शुभारंभ किया था। लेकिन तब से लेकर आज तक उसे संचालित नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि वन विभाग ने आनन फानन में सफारी का शुभारंभ तो कर दिया लेकिन बाद में शायद इसे संचालित करना ही भूल गए। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में श्योपुर की सीमा के भीतर पर्यटन को बढ़ावा देने को भले ही चंबल सफारी शुरू करने की योजना हो, लेकिन शुभारंभ के 13 साल बाद भी चंबल में बोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। जबकि बड़े जोर-शोर से अभयारण्य प्रबंधन और इको टूरिज्म बोर्ड ने तत्कालीन तत्कालीन दिवंगत वन मंत्री सरताज सिंह से शुभारंभ कराया था लेकिन उसके बाद दोनों विभागों के अफसर शायद चंबल सफारी को संचालित कराना भूल गए। जिसके चलते सैलानियों को श्योपुर की सीमा में चंबल में बोटिंग का इंतजार पहाड़ सा लंबा होता जा रहा है। श्योपुर के पाली घाट से उत्तरप्रदेश के चकरनगर तक 435 किलोमीटर लंबाई में फैले राष्ट्रीय चंबल घडियाल अभयारण्य के अंतर्गत श्योपुर जिले की सीमा में चंबल नदी में पर्यटकों को बोटिंग का लुत्फ प्रदान करने के लिए चंबल सफारी की प्लानिंग की गई थी। अभयारण्य प्रबंधन और मध्यप्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से इसकी रूपरेखा तय की गई। जिसके तहत पाली घाट से रामेश्वर त्रिवेणी संगम तक चंबल सफारी में बोटिंग कराई जाने की कार्ययोजना थी। इसके लिए 18 नवंबर 2011 को पाली घाट पर इसका शुभारंभ भी समारोहपूर्वक किया गया। जिसमें तत्कालीन एवं दिवंगत वनमंत्री सरताज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। वहीं इको टूरिज्म व वनविभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। हालांकि तत्कालीन वनमंत्री और वन विभाग के तत्कालीन अफसरों ने बड़े-बड़े दावे किए, लेकिन उद्घाटन के 13 साल बाद भी चंबल सफारी शुरू नहीं हो सकी है।

पशुओं के लिए बड़े काम की हैं अन्ननास की पत्तियां

भोपाल। पशुपालकों के लिए सबसे बड़ी समस्या पशुओं के चारे की होती है। पशुपालन हमेशा इस फिक्र में रहता है कि अपने पशु के लिए सालभर चारे की व्यवस्था कैसे करें। अगर दुधारू पशु हो तो यह चिंता और भी गहरी हो जाती है। दुधारू पशुओं को हर तरह का चारा नहीं खिला सकते। दुधारू पशुओं को वैसा ही चारा दिया जाता है जो उसकी सेहत के लिए उपयुक्त हो। हारा चारा हमेशा उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में किसान हर उस विकल्प पर गौर करता है जो उसके दुधारू पशु के लिए सेहतमंद और आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके लिए आईसीएआर ने एक अच्छी जानकारी दी है। यह जानकारी अन्नानास के पत्तों को लेकर है। आईसीएआर ने बताया है कि अन्नानास के पत्तों को वैज्ञानिक तरीके से प्रीजर्व करके चारा बनाया जा सकता है। इस चारे को टोटल मिक्स्ड राशन कहा जाता है। टीएमआर को हिंदी में कुल मिश्रित राशन कहते हैं जिसमें एक साथ कई खाद्य पदार्थों को मिलाया जाता है और पशुओं को खिलाया जाता है. खासकर गाय और भैंसों को। टीएमआर में चारे के साथ साबूत कपास के बीज, अनाज, प्रोटीन, खनिज और विटामिन मिलाए जाते हैं। आईसीएआर के मुताबिक, टीएमआर बनाने के लिए अन्नानास के पत्तों को इस्तेमाल किया जा सकता है। अन्नानास के पत्ते चारे में प्रयोग करने के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये कि ये पत्तियां अधिक मात्रा में पाई जाती हैं।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)